



दैनिक समाचार पत्र

हक की बात, बुलंदी के साथ

विन्ध्य टाइगर

हम जादूगर है, ट्रिक करते हैं: गहलोत

5

बहुत तकलीफ में हैं हिटमैन

6



हमारी सेना पाक को घुटनों पर लाई : पीएम

पीएम बोले-अब मोदी के नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला राजस्थान दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने 26 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सीगात दी। साथ ही देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन सभी रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया था।

अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सभा को भी संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने आतंकवादी देश पाकिस्तान पर भी तगड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा- मेरी नसों में अब गरम लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को भारत के पानी का हक नहीं



मिलेगा, यह हमारा संकल्प है। कोई भी ताकत इस संकल्प को रोक नहीं सकती।

पीएम मोदी ने कहा- एक ओर हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं, वहीं नदियों को जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। इससे यहां की धरती और किसानों को लाभ मिलेगा। राजस्थान की वीर भूमि हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बढ़कर कुछ नहीं है। 22 तारीख को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था।

गोलियां पहलगाम में चली थीं, लेकिन वे गोलियां 140 करोड़ देशवासियों के सीने को छलनी कर गई थीं। इसके बाद देश ने संकल्प लिया कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। आज हमारी सेना के शौर्य से हम उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा- हमने

22 मिनट में आतंकियों के नौ सबसे बड़े ठिकाने नष्ट कर दिए। जब सिंदूर बारूद बन जाता है, तो उसका नतीजा क्या होता है, यह पाकिस्तान को बता दिया गया है। साथियों, यह संयोग ही है कि पांच साल पहले जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, तब मेरी पहली जनसभा बीकानेर में हुई थी। यह वीर भूमि का प्रभाव ही है कि ऐसा संयोग फिर बना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मेरी पहली जनसभा बीकानेर में हो रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद चूरू में मैंने कहा था- शपथ है मुझे इस मिट्टी की कि मैं देश को मिटने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा...। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि देश के कोने-कोने में तिरंगा यात्राओं का हजूम उमड़ पड़ा है। जो सिंदूर मिटाने निकले

थे, उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज उनसे एक-एक कतरे का हिसाब चुकाया गया है। जो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा, आज वे अपने घरों में दुबके बैठे हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वे मलबे के ढेर में दबे पड़े हैं।

पीएम मोदी ने कहा- यह प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय का नया स्वरूप है। यह ऑपरेशन सिंदूर है। यह आक्रोश नहीं, समर्थ भारत का रौद्र रूप है। यह भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर हमला किया था, अब सीधा सीने पर प्रहार किया गया है। आतंक का फल कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है और यही नया भारत है।

पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने तीन नियम तय किए हैं।

नर्मदापुरम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी: डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नर्मदापुरम जिले की भूमि उपजाऊ एवं समृद्ध है, यहां कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए शासन कृत-संकल्प है। नर्मदापुरम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। आने वाले समय में नर्मदापुरम औद्योगिक रूप से विकसित जिला बनेगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सिवनी मालवा में 97.07 करोड़ के 31 कार्यों का लोकार्पण एवं 102.94 करोड़ के 48 कार्यों का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सिवनी मालवा में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदापुरम जिला ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे देश की पहचान कृषि से होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने



किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं श्रमिक सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई हैं। मध्यप्रदेश शासन भी गरीब वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति जियो और जीने दो पर आधारित है। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा प्रदेश देश के मध्य में है इसलिए हमारी जवाबदेही और

जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने इस बारे 2600 रूपए प्रति क्विंटल के मान से किसानों से गेहूं खरीदा है। आने वाले समय में हम 05 लाख के सोलार पंप पर 90 प्रतिशत अनुदान देंगे। सोलार पंप में जो मीटर लगेगा उससे किसानों को निःशुल्क में बिजली मिलेगी और आने वाले समय में सरकार किसानों से बिजली भी खरीदेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 26 मई को नरसिंहपुर जिले में किसान उद्योग समगम मेले का आयोजन किया जाएगा।

आसिम मुनीर कट्टरपंथी, पहलगाम आतंकी हमला उसी का नतीजा: जयशंकर

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तीखा हमला बोला और उन्हें धार्मिक कट्टरपंथी बता दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला उस कट्टरपंथी सोच का ही नतीजा है। नीदरलैंड के एक समाचार पत्र के साथ बातचीत में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। पहलगाम आतंकी हमले पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में बर्बर आतंकी हमला किया गया,



जहां 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई। यह हमला कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर किया गया था क्योंकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है। हमले के द्वारा धार्मिक भेदभाव को बढ़ाने की कोशिश की गई और लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख हैं, वो खुद धार्मिक कट्टरपंथी हैं। पहलगाम में

हुआ आतंकी हमला उसी कट्टरपंथी सोच का नतीजा है।

विदेश मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन हैं और टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। उन्होंने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 2023, 2024 में टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जयशंकर ने कहा कि हमने पहलगाम आतंकी हमला करने वाले लोगों की पहचान की और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है और उसके बाद उन्हें निशाना बनाया।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार, सुबह तकरीबन 11.30 बजे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। चीफ जस्टिस को मेल के जरिए धमकी मिली है। इसके बाद दो बजे तक के लिए हाईकोर्ट खाली करवा दिया गया। वहीं चंडीगढ़ के एलांते मॉल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर आपरेशन सेल, बम डिटेक्शन टीम और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और पूरे मॉल को खाली करवाया गया।

सलमान की सुरक्षा में चूक, दो दिन में घर में घुसे दो अंजान शख्स

मुंबई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दो दिन के भीतर ही दो अंजान लोगों ने सलमान खान के घर में घुसने की कोशिश की है। पहले 20 मई को एक पुरुष ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी, जिसे सिक्योरिटी गाार्ड्स ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वहीं अगले दिन यानी 21 मई की रात एक महिला ने भी सलमान के घर में घुसने का प्रयास किया। गुरुवार सुबह मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जांचिए क्या है पूरा मामला। सबसे पहले मंगलवार को सलमान खान की सिक्योरिटी को

चकमा देकर एक शख्स ने उनके घर में घुसने की कोशिश की। यह युवक कार में पीछे छिपकर सलमान के बिल्डिंग परिसर में घुसने में कामयाब भी हो गया। हालांकि, सिक्योरिटी गाार्ड्स ने इसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, जो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि युवक को पहले सुबह सलमान के घर के आसपास घूमते देखा गया। वहां तैनात एक पुलिसकर्मी ने उसे जाने के लिए कहा। बाद में शाम को युवक बिल्डिंग में रहने वाले एक

व्यक्ति की कार में बैठकर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा। हालांकि, पुलिस ने उसे फिर से रोक लिया। पृष्ठताछ के दौरान युवक ने बताया कि वह अभिनेता से मिलना चाहता था। इसके बाद बुधवार रात एक अंजान महिला ने भी सलमान के घर में घुसने की कोशिश की। मुंबई पुलिस के मुताबिक, ईशा छाबड़ा नाम की महिला ने रात को लगभग 330 बजे सलमान के घर में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि महिला बिल्डिंग की लिफ्ट से सीधे सलमान के फ्लैट तक जा पहुंची। जहां गैलेक्सी अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्डों ने उस महिला को पकड़कर बांद्रा पुलिस को सौंप दिया।

ज्योति की चार दिन की रिमांड बढ़ी

हिसार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की वूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ज्योति की चार दिन की रिमांड बढ़ा दी है। हिसार पुलिस ज्योति को गुरुवार सुबह साढ़े 9 बजे कोर्ट लाई थी। करीब डेढ़ घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली। जिसके बाद हिसार पुलिस को उसकी 4 दिन का रिमांड मिल गई। इस दौरान किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की। पेशी के वक्त ज्योति से उनके पिता हरीश मल्होत्रा को नहीं मिलने दिया गया। ज्योति 16 मई को गिरफ्तार हुई थी।

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम सुनवाई पूरी

कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को तीन मुद्दों पर अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया। जिसमें अदालतों द्वारा वक्फ, वक्फ बाई यूजर या वक्फ बाई डीड घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवंई और न्यायमूर्ति आंग्रिस्टिन जॉर्ज मसीह को पीठ ने अंतिम आदेश सुरक्षित रखने से पहले करीब तीन दिन

तक वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं, जो संशोधित वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। केंद्र ने इस अधिनियम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और संवैधानिकता की धारणा के इसके पक्ष में होने के मद्देनजर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

दुनिया आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ आए: रणधीर

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को साप्ताहिक ब्रीफिंग में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की रवानगी समेत तमाम मुद्दों पर जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के लिए एक साथ आए।

उन्होंने कहा कि हम दुनिया से आग्रह करना चाहते हैं कि वे सीमा पार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार

लोगों को जवाबदेह ठहराएं। पाकिस्तान पिछले 40 वर्षों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को अंजाम दे रहा है। उसके माध्यम से उजागर करने की आवश्यकता है। उसे भारत के खिलाफ किए गए आतंकी हमलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसलिए सात प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। तीन प्रतिनिधिमंडल रवाना हो चुके हैं। यह एक राजनीतिक मिशन है।

चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच विपक्षीय वार्ता पर उन्होंने कहा कि हमने कुछ रिपोर्टें देखी हैं। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के साथ बातचीत पर हमने जानकारी दी थी। विदेश मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया। वे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्री ने हाल ही में झूठी और निराधार रिपोर्टों के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास

पैदा करने के प्रयासों को दृढ़ता से अस्वीकार करने का भी स्वागत किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को समाप्त करने का श्रेय लेने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कि अपनी पिछली ब्रीफिंग में मैंने इस पर बात की थी। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आप हमारी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच कोई भी जुड़ाव द्विपक्षीय होना चाहिए।

तो दोपहर के बाद भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते अंधेरा छ गया। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई

हफ्ते भर में ही कोरोना ने बढ़ा दी टेंशन

नई दिल्ली। कोरोना का खतरा दुनियाभर में एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस नई लहर का प्रकोप एशियाई देशों में सबसे ज्यादा है। हांगकांग-सिंगापुर और चीन के कई हिस्सों से शुरू हुई कोरोना की ये लहर अब भारत में भी दस्तक दे चुकी है। 22 मई, गुरुवार तक देश में कुल 257 एक्टिव केस हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरह से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में भी लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करते रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 12 मई से 19 मई के बीच सप्ताह में 164 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में कुल सक्रिय मामले 257 हो गए। केरल में सबसे अधिक 95 मामले हैं, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 69 मामलों की वृद्धि है। इसके बाद तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 मामले हैं। देश के सभी राज्यों में कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट किया गया है। गुरुवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक ओडिशा में ढाई साल के अंतराल के बाद कोविड-19 का एक नया मामला सामने आया है।

दिल्ली में हार के बाद आप में बड़े बदलाव

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी ने नई जिम्मेदारियों की घोषणा करते हुए कई राज्यों के लिए प्रभारियों और सह-प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। दिलीप पांडे को पार्टी का ओवरसीज कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। जितेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश, राजेश गुप्ता को कर्नाटक, ऋतुराज गोविंद को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सूची के अनुसार, उत्तराखंड के प्रभारी महेंद्र यादव बनाए गए हैं। केरल में शेली ओबेरॉय, महाराष्ट्र में प्रकाश जाजवाल, राजस्थान में धीरेश टोकस, तेलंगाना में प्रियांका कक्कड़, तमिलनाडु में पंकज सिंह और लद्दाख में प्रभाकर गौर को प्रभारी बनाया गया है।

किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़

एक जवान बलिदान, कुछ सैनिक घायल



जम्मू। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चटरू के सिंहपोरा इलाके में में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षाबलों ने गोलीबारी के बाद तीन से चार आतंकियों को घेर लिया। गोलीबारी में एक जवान बलिदान हो गया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अन्य घायल सैनिकों का उपचार उधमपुर सेना अस्पताल में किया जा रहा है।

किश्तवाड़ आतंकी मुठभेड़ में शहीद सैनिक की पहचान सिपाही गायकवाड़ संदीप पांडुरंग निवासी करानाडी तहसील अकोला जिला अहमदनगर महाराष्ट्र के रूप में हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली कि चटरू के सिंहपोरा इलाके में आतंकी छिपे हैं। सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को धिरा देख सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। किश्तवाड़ के सब डिवीजन चटरू के सिंहपोरा इलाके में मुठभेड़ हुई।

देश में कई जगह भारी बारिश, घरों में पानी... सड़के बंद

नई दिल्ली। भीषण गर्मी के बीच अचानक बदले मौसम और बारिश के कारण लोगों को बढ़ते तापमान से राहत तो मिली, लेकिन बारिश का कहर भी दिखा। घरों में पानी घुसने और सड़कें बंद होने की तस्वीरें हालात बयां कर रही हैं। दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से जानमाल का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर दिन में रात जैसा नजारा दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते दस्तक देने जा रहा मानसून दहलीज पर खड़ा है।

अगले चार से पांच दिनों के दौरान केरल में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। लेकिन मानसून के पहुंचने से पहले पश्चिमी



घाट के कुछ हिस्सों, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। पालघर जिले के नाला सोपारा में भारी बारिश के कारण एक घर का छज्जा गिर गया, जिसमें दो लोगों को बचा लिया गया। पश्चिमी हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में सुबह धूप खिली

हिस्सों में मानसून से पहले की बारिश हो रही है। पुणे और बंगलूरू जैसे प्रमुख शहरों में भारी बारिश में जलभराव के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। कई घरों में अब भी बारिश का पानी घुसा हुआ है। कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हैं तो बिजली भी गुल है।

कर्नाटक के तटीय और घाटी क्षेत्रों में 204.5 मिमी से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही वज्रपात और भारी वर्षा भी संभावित है और 204.4 मिमी तक बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड,

मराठवाड़ा, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ 64.5 से 115.5 मिमी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र तल से औसतन 1.5 किमी ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक पश्चिम पूर्व ट्रफ लाइन मध्य पाकिस्तान से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तरी बांग्लादेश तक फैली हुई है। इस ट्रफ के प्रभाव से 21 से 26 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं, बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना है।

एनसीएल ग्राउंड में कचरा गाड़ियों का किया गया भौतिक सत्यापन

कमिश्नर, महापौर, अध्यक्ष सहित पार्षद रहे मौजूद, पार्षदों ने कंपनियों की गाड़ियों का भौतिक सत्यापन करने का लगाया आरोप

सिंगरौली। नगर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन कर रही कंपनी की गाड़ियों का आज नगर निगम अमला ने एनसीएल ग्राउंड में भौतिक सत्यापन करवाया गया। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत घर-घर कचरा प्रबंधन में लगी हुई गाड़ियों को एनसीएल ग्राउंड में इकट्ठा किया गया और पार्षदों की मौजूदगी में भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान महापौर रानी अग्रवाल, अध्यक्ष देवेश पांडेय, कमिश्नर डीके शर्मा सहित पार्षद मौजूद रहे।

दरअसल नगर निगम परिषद बैठक में पार्षदों का आरोप था कि घर-घर कचरा संग्रहण और मृत् मवेशियों को उठाने के लिए सिटाडेल कंपनी ने 45 से 50 गाड़ियां ही लगा कर रखीं हैं। जिससे प्रतिदिन हर बाड़ों से घर-घर कचरे का संग्रहण नहीं हो पा रहा। कौन गाड़ी कहाँ जा रही है इसका निर्धारण भी कराया जाए, इसके बाद परिषद ने सिटाडेल में लगी गाड़ियों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। जहाँ आज कचरा वाहन और मृत्



मवेशी वाहनों को भौतिक सत्यापन कराया गया। लेकिन सिटाडेल कंपनी के इस भौतिक सत्यापन से संतुष्ट नहीं हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि अन्य कंपनियों में लगी गाड़ियों को भी लाया गया है जो बिल्कुल गलत है। नगर निगम कमिश्नर डीके शर्मा ने बताया कि पार्षद गणों ने परिषद की बैठक के दौरान कचरा प्रबंधन कर रही। कंपनी सिटाडेल पर कम गाड़ियां लगाने की शिकायत की थीं। जिसके बाद परिषद ने कचरा संग्रहण और मृत् जानवरों को ले जाने के लिए

कंपनी ने कितनी गाड़ियां लगाई गई हैं उनके भौतिक सत्यापन की मांग की गई थी। जिस पर आज भौतिक सत्यापन किया गया है। प्राथमिक रूप से सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा कंपनी ने कहा था। इस दौरान खुर्शीद आलम, पार्षद सीमा जायसवाल, राम नरेश शाह, अनिल बैस, प्रेम सागर मिश्रा, शेखर सिंह, राम गोपाल पाल, रूकमन देवी, बंतो कौर, राम मिलन भारती, परमेश्वर पटेल, नगर निगम के उपायुक्त आरपी बैस, पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन गुप्ता, अमित यादव,

सीटाडेल अधिकारी रावेन्द्र उपस्थित रहे।

पार्षदों ने कंपनियों में लगे वाहनों को लाने का आरोप

नगर निगम के पार्षद परमेश्वर ने आरोप लगाया की कचरा प्रबंधन का काम कर रही कंपनी दूसरी जगह से बाहर की गाड़ियां लाकर यहां खड़ी की गई हैं। कंपनी प्रबंधन हर महीने एक करोड़ 20 लाख रुपए कचरा प्रबंधन के नाम पर ले रहा है, लेकिन शहर कचरे के ढेर में है और नगर निगम के अधिकारी

इनसे मिले हुए हैं। कंपनी ने एनसीएल ग्राउंड पर आज 75 गाड़ियां भौतिक सत्यापन के लिए लाई थी, जिनमें से कई गाड़ियां कबाड़ हैं और कई गाड़ियां एनसीएल और एनटीपीसी से लाई गई हैं। जिन पर नगर निगम लिखवाया गया है।

इनका कहना है

तीनों जोन में लगी गाड़ियों का सत्यापन कराया गया। कौन सा वाहन किस वार्ड में जाएगा, वाहन में कौन ड्राइवर रहेगा, इसकी जानकारी वार्ड पार्षदों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कंपनी लापरवाही बरतती है तो कार्रवाई की जाएगी।

देवेश पांडेय अध्यक्ष, नगर निगम सिटाडेल कंपनी के मैनेजर ने कहा है कि नगर निगम के साथ जो अनुबंध किया है उसके हिसाब से गाड़ियां लगी हैं और कंपनी नियम के अनुसार काम कर रही है।

रावेन्द्र सिंह मैनेजर, सिटाडेल कंपनी

बदहाल सिंगरौली में महोत्सव मनाना सिंगरौलीवासियों का अपमान : राजेश

सिंगरौली। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा की जिले में जिस तरह से सड़क दुर्घटना से लगातार मृत्यु हो रही है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर एवं दवा की कमी के कारण मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं। प्रदूषण के मामले में सबसे आगे आना वाला क्षेत्र एवं जिले में तमाम तरह की कंपनियां होने के बाद भी जिले के युवा रोजगार के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। ऐसे में जिला प्रशासन एवं म.प्र. सरकार के द्वारा जनता के टैक्स के कई करोड़ रुपये



खर्च करके सिंगरौली महोत्सव का कार्यक्रम मनाना जिलेवासियों का अपमान है। क्योंकि जिले के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तत्स रहे हैं। जिले में ना तो आजतक हाईवे का निर्माण हो पाया, ना ही रेलवे की अच्छी व्यवस्था हो पाई। हवाई अड्डे की बात किया जाए तो वर्ष 1960 से

चल रहे प्रोजेक्ट को हवाई पट्टी में तब्दील कर दिया गया फिर किस बात का सिंगरौली महोत्सव। इस महोत्सव को मनाने से पहले एक बार सिंगरौली की जनता का हालातों को देखना चाहिए और उनसे सहमति लेना चाहिए, क्योंकि देश अब आजाद है, ऐसा काम ब्रिटिश शासन में हुआ करता था की अंग्रेजों का जो इच्छा करता था वो वही करते थे। ब्रिटिश शासन में देश की जनता की बदहाली से कोई लेना-देना नहीं था। उसी तरह से आज की शासन एवं प्रशासन जिले में कार्य कर रही है।

मानसून को दृष्टिगत रखते हुये तीन माह का राशन एकमुश्त आवंटित करने के आदेश जारी

सिंगरौली। जिला आपूर्ति अधिकारी पीसी चन्द्रवंशी ने बताया कि आगामी मानसून सीजन में संभावित बाढ़ के कारण राशन सामग्री के परिवहन, भंडारण एवं वितरण में आने वाली समस्याओं के निराकरण एवं पात्र परिवारों को समय-सीमा में राशन सामग्री उपलब्ध करने के लिए एनएफएस तथा पीएमजीकेवाई अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों को माह जून से अगस्त तक की एकमुश्त राशन सामग्री के आवंटन, उठाव एवं वितरण किया जाने के लिए राज्य शासन द्वारा सभी उपखण्ड अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

एनटीपीसी विंध्याचल ने निकली रैली, स्वच्छ भारत की ओर एक और सशक्त कदम

सिंगरौली। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत एनटीपीसी विंध्याचल ने आज अपने टाउनशिप परिसर में एक प्रेरणादायक स्वच्छता रैली का आयोजन किया।

इस रैली में एनटीपीसी के अधिकारियों –कर्मचारियों उनके परिजनों के साथ-साथ सीआईएसएफ, यूनिनय तथा एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। रैली का नेतृत्व ई सत्य फणि कुमार कार्यकारी निदेशक ने किया। इस अवसर पर अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिनमें संजीव



कुमार साहा प्रचालन एवं अनुसंधान, डीके अग्रवाल सविदा एवं सामग्री, राजशेखर पाला सहित अन्य शामिल रहे। रैली के दौरान टाउनशिप में स्वच्छता के नारे गुंज उठे, जिन्होंने न केवल वहां मौजूद लोगों को प्रेरित किया,

बल्कि साफ-सफाई, पर्यावरणीय चेतना और सामाजिक भागीदारी के महत्व को भी उजागर किया। यह आयोजन एनटीपीसी विंध्याचल की स्थायी विकास और स्वच्छ भारत के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

एनटीपीसी विंध्याचल ने जल संरक्षण की दिशा में उठाया बड़ा कदम, सूर्या नाला पर बनाया चेक डैम

सिंगरौली। एनटीपीसी विंध्याचल ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और अहम पहल करते हुए सूर्या नाला पर चेक डैम का निर्माण किया है। यह नाला रिहंद जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और आसपास के जल स्रोतों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह चेक डैम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाया गया है, जो जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और जनसहभागिता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस चेक डैम का उद्घाटन



संजीव मेहरा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर एजे राजकुमार महाप्रबंधक तथा ईएमजी और ऐश डाइक प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। एनटीपीसी विंध्याचल की यह पहल न केवल जल

गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी, बल्कि यह जल संरक्षण में औद्योगिक संस्थानों की सक्रिय भूमिका का भी प्रमाण है। यह परियोजना आने वाले समय में क्षेत्रीय पारिस्थितिकी और जल आपूर्ति को स्थायित्व प्रदान करेगी।

मण्डल खुटार के तेलदह में शौर्य तिरंगा यात्रा हुई सम्पन्न

सिंगरौली। ऑपरेशन सिंदूर के अपार सफलता पर सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में भारतीय जनता मण्डल खुटार द्वारा आयोजित शौर्य तिरंगा यात्रा तेलदह में निकाली गई। जिसमें मुख्य रूप से भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमलेश बैस, भाजपा मण्डल अध्यक्ष मनोज शाह, मण्डल उपाध्यक्ष जय प्रसाद बैस, महेन्द्र कुमार पाण्डेय, रामलल्लू शाह, महामंत्री अरविन्द बखोर, मण्डल मंत्री विजय कुमार गुप्ता, बद्री प्रसाद बैस, रामलल्लू कुशवाहा, देवलाल यादव, बंशीलाल यादव, रामविशाल साकेत, अम्बिका प्रसाद दुबे, मेवालाल केवट, लल्लु साकेत, सुनीता साकेत एवं अंबिका प्रसाद बैस सहित कई ग्रामीण जनों सहभागिता निभाई।



बगदरा अंचल के कई गांव में 72 घंटे से बिजली गुल पशुओं को भी नहीं पिला पा रहे हैं ग्रामीण पानी, जंगल में कई बिजली खंभे टूटे

सिंगरौली विद्युत सब स्टेशन क्षेत्र चितरंगी के उप तहसील बगदरा अंतर्गत एक दर्जन गांवों में पिछले 72 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है। बताया जा रहा है कि करीब 10 की संख्या में अलग-अलग स्थान पर बिजली के पोल तूफान के चलते पिछले कई दिनों से टूटे हुए गए थे। जिसके कारण बिजली सप्लाई बंद है। जानकारी के अनुसार बगदरा

उप तहसील क्षेत्र के खामहारडोह, रेही, कुलकवार, बगदरा, करौंदिया, गोपाल, फुटहडवा, रमपुरवा, बरगवां, बकिया सहित कई गांव में पिछले 72 घंटे से बिजली सेवा पूरी तरह से प्रभावित है। बताया जा रहा है कि करीब 10 की संख्या में कई अलग-अलग स्थान में बिजली के खंभे तूफान के चलते टूट गया। जिसके कारण विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। बिजली के बंद होने से इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों को जो

बोरवेल के भरोसे हैं, वह भी पानी के लिए भटक रहे हैं। मवेशियों के सामने भी पानी का संकट खड़ा हो गया। हालांकि एमपीईबी ग्रामीण के कार्यालय अभियंता ने बताया है कि बिजली आपूर्ति बाहर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। कई खंभे टूट जाने के कारण या समस्या उत्पन्न हुई है। आज दिन गुलवारा के देर शाम तक में बिजली सेवा बहाल हो जाएगी। कुछ गांव की आपूर्ति बहाल हो गई है।

दिन भर छाए रहे बादल, गर्मी और उमस से मिली राहत

सिंगरौली मई महीने भीषण गर्मी से पूरा जनजीवन जूझ रहा। इस बीच आज दिन गुरुवार को दिन भर बादल छाए रहे। दिन भर सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए। गत दिवस बुधवार को दोपहर हुई बारिश और दूसरे दिन बादल छाने की वजह से गर्मी और उमस का असर काफी कम रहा। सब्जी का व्यवसाय करने वाले किसान बारिश होने और बदल छाने से राहत महसूस कर रहे हैं। बता दे की बोते दिन बुधवार को आधे घंटे तेज बारिश होने और दूसरे दिन बादल छाए रहने से मौसम फिर भी खुशगवार बना रहा। गर्मी और उमस काफी कम रही। एक दिन की कुछ ही घंटों की बारिश

ने बिजली की मांग को भी थोड़ा कम कर दिया। वहीं तेज हवा नहीं चलने से ट्रिपिंग की समस्या का सामना भी कम ही करना पड़ा। पिछले दो दिन से जिले का मौसम राहत भरा रहा है और तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चल रहा है। अगर एक-दो दिन और अच्छी बारिश हो गई तो मौसम में और भी सुधार हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटा या उससे अधिक हो सकती है। यह स्थिति 24 मई तक रहेगी। वहीं 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। हालांकि इस बार नौतपा में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के कारण थोड़ी कम गर्मी रहेगी।

समग्र ई-केवाईसी की प्रगति कम होने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

सिंगरौली। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को बिना किसी असुविधा के प्राप्त हो, इसके लिए समग्र आईडी का ई-केवाईसी जिले में अभियान चलाकर किया जा रहा है। कलेक्टर के द्वारा परिवार समग्र आईडी से आधार लिंक के कार्य में कम प्रगति आने पर नाराजगी जाहिर करते हुये समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नग्न आयुक्त सहित नगर परिषद बरगवां एवं सरई के सीएमओ को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 मई तक प्रत्येक परिवार का समग्र ई-केवाईसी किया जाना सुनिश्चित कराये। उन्होंने निर्देशित किया कि समग्र का ई-केवाईसी कराने के लिए नागरिकों प्रेरित करने के लिए इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराये साथ ही इस कार्य पर लगातार मॉनीटरिंग भी करते रहे।

पत्नी और बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी पति गिरफ्तार ईनामी आरोपी 2 साल से चल रहा था फरार, विंध्यनगर पुलिस की कार्यवाही

सिंगरौली। विन्ध्यनगर थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में 2 साल से फरार इनामी आरोपी को डिंडोरी से गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही 21 जून 2023 को दर्ज एक शिकायत के आधार पर की गई है। आरोपी पर आरोप हैं पत्नी और बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और जीवित रहते पत्नी को प्रताड़ित करता था। पत्नी की आत्महत्या करने के बाद से ही वह फरार हो गया था। और नंबर बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था।

मिली जानकारी के अनुसार विंध्यनगर थाना पुलिस ने दो साल से फरार इनामी आरोपी को डिंडोरी जिले के एक गांव से गिरफ्तार किया है। विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी ने बताया कि 21



जून 2023 को इस बात की सूचना आई थी की निर्मला विश्वकर्मा नाम की महिला ने अपने चार साल के बेटे राजेश विश्वकर्मा के साथ एनटीपीसी की नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली है। मामले की जब विवेचना की गई तो पता चला कि मृतक महिला का पति रामेश्वर विश्वकर्मा आए दिन पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट कर रहा था और उसे प्रताड़ित कर रहा था जिसका पहले से न्यायालय में मामला चल रहा था। इसी बीच महिला ने अपने चार साल के बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। विवेचना के दौरान पता चला इस आत्महत्या की वजह उसका पति है आत्महत्या करने के दिन से ही पति फरार हो गया था। जिसकी लगातार तलाश

सम्पर्क में था और कहां-कहां अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया उसकी जांच की जा रही है। इस कार्यवाही में निरीक्षक अर्चना द्विवेदी, उप निरीक्षक शीतल यादव, सहायक उप निरीक्षक सुनील दुबे, प्रधान आरक्षक पंकज सिंह, वृजेश सिंह, रुकमणी तिवारी, अमलेश कुमार, आरक्षक प्रताप कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आरोपी पुलिस से बचने के लिए हर बार अपनी पहचान छुपा लेता था। और पिछड़े इलाकों में रहता था। कई बार तो आरोपी ने स्वयं को राजस्व विभाग का आरआई होना बताया था। आरोपी बचने के लिए कम पड़े लिखे लोगों की आईडी लेकर सिम निकलवा लेता था। जिससे पुलिस

उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। आरोपी इतना शातिर था कि वह एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक अपराधों को अंजाम दे चुका है। वह भोले-भाले लोगों को नौकरी के नाम पर ठगी करता था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह फरार हो जाता। इसके बाद तात्कालिक एसपी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की घोषणा की थी।



अभियान चलाकर 31 मई तक ई-केवाईसी का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करायें : कलेक्टर

समग्र ई-केवाईसी के लिए विशेष अभियान चलाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

सीधी। जिले में समग्र ई-केवाईसी की प्रगति को लेकर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई। कुछ क्षेत्रों में ई-केवाईसी की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता पर लें और समयबद्ध रूप से लक्ष्यों को पूर्ण करें।

कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे समस्त हितग्राहियों के साथ-साथ जिले के सभी व्यक्तियों का भी ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए गये हैं। वर्तमान में जिले की ई-केवाईसी प्रगति कम होने से उसे अभियान के रूप में पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। ई-केवाईसी के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने-अपने अनुभाग के लिए नोडल अधिकारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व शहरी क्षेत्र में सीएमओ नगरी निकाय सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।



ई-केवाईसी कार्य को पूर्ण कराने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम समग्र पोर्टल से हटाने के लिए 07 दिन का अभियान चलाकर 31.05.2025 तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करेंगे। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतिदिन कम से कम 15-20 पंचायत में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए दिनांकवार/पंचायतवार कैलेंडर तैयार कर ग्रामसभा का आयोजन करवायेंगे। आयोजित ग्रामसभा के लिए एक-एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे। आयोजित ग्रामसभा में खाद्य विभाग से प्राप्त सूची का वाचन करेंगे तथा वाचन उपरांत

हितग्राहियों की ई-केवाईसी करते हुए शेष हितग्राही जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही निम्न बिन्दुओं पर सूची तैयार कर जनपद/नगरीय निकाय में जमा कराते हुए समग्र पोर्टल से उनके नाम डीलिट कराना भी सुनिश्चित करेंगे जैसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है, व्यक्ति जो अन्य स्थान पर चले गए हैं, महिला जिनकी विवाह हो चुका है, व्यक्ति जिनके आधार अन्य राज्य के हो, डबल समग्र आईडी वाले व्यक्ति। आयोजित होने वाली ग्रामसभा में उचित मूल्य टुकान के विक्रेता, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, आँगनवाड़ी

कार्यकर्ता के साथ-साथ ग्राम स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया से शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुँचाया जा सकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि वे आमजन को ई-केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में जागरूक करें और ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रगति की अगली समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण नहीं करने के कारण 27 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण नहीं करने के कारण संबंधित अधिकारियों को एक वेतनवृद्धि रोकने हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 20 मई को समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री जल संसाधान विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी जिला हाथकरघा विभाग, श्रम पदाधिकारी श्रम आयुक्त कार्यालय, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग उपखण्ड (मझौली, सीधी, रामपुर नैकिन), सहायक यंत्री मकैनिकल विंग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

विभाग उपखण्ड सीधी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (सीधी, रामपुर नैकिन, कुसमी, मझौली, सिहावल), मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद चुरहट, खण्ड चिकित्सा अधिकारी विकास खण्ड (रामपुर नैकिन, मझौली, सिहावल, कुसमी, चुरहट, सीधी), खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन, वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र (टमसार, व्यौहारी बफर, दुबरी संजय टाईगर रिजर्व सीधी) की स्थिति संतोष जनक नहीं पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

उपरोक्तानुसार विभाग की ग्रेडिंग सी, डी होने के जिले की भी ग्रेडिंग प्रभावित हो रही है।

शिकायतों के निराकरण में रूचि नहीं लिये जाने के कारण शिकायतें अकारण उच्च स्तर पर अंतरित हो रही हैं। उपरोक्त कृत्य से स्पष्ट है कि संबंधित के द्वारा पदवी दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है, जो म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 9 (क) के प्रतिकूल है। नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के अंदर उपरोक्त शिकायतों के निराकरण कर प्रतिवेदन सहित जवाब प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित के विरुद्ध कयों न एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया जावे। नियत अवधि में जवाब प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

लोक सेवा केंद्रों की तकनीकी रूप से पात्र एवं अपात्र निविदाकारों की दावा आपत्ति कार्यालयीन मेल के माध्यम से 23 मई तक आमंत्रित

सीधी। अध्यक्ष लोक सेवा निविदा समिति एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज ने जानकारी देकर बताया है कि जिले में संचालित एक लोक सेवा केंद्र रामपुर नैकिन एवं एक नवीन लोक सेवा केन्द्र मडवास के लिये कार्यालयीन विज्ञप्ति दिनांक 15 जनवरी 2025 के द्वारा उक्त लोक सेवा केंद्रों की निविदा दिनांक 04

फरवरी 2025 तक आमंत्रित की गई थी। दिनांक 06 फरवरी 2025 को समय 3.30 बजे प्राप्त निविदाओं को खोले जाने पर कुल 258 निविदाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से लोक सेवा केन्द्र रामपुर नैकिन में 138 तथा लोक सेवा केन्द्र मडवास में 120 निविदाओं की तकनीकी निविदा खोला जाकर परीक्षण उपरान्त सम्पन्न सूची अनुसार 193 निविदाओं में कमियां पाई गई हैं,

जिसके कारण उन्हें तकनीकी रूप से अपात्र एवं 65 निविदाओं में कोई कमियां नहीं पायी गई हैं, जिसके कारण उन्हें तकनीकी रूप से पात्र पाया गया है। आर.एफ.पी की कण्टिका 2.15.3 अनुसार दो दिवस अर्थात् दिनांक 23.05.2025 को सायं 4 बजे तक तकनीकी रूप से पात्र/अपात्र निविदाकारों की दावा आपत्ति कार्यालयीन मेल के माध्यम से आमंत्रित की गई है।

फाइलों को देखकर जारी होते हैं वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र

जिला परिवहन कार्यालय में मनमानी, चल रहा बाबू राज

सीधी जिले में परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस तक ही सीमित नहीं है। बल्कि भ्रष्टाचार की आंच वाहनों के फिटनेस जांच तक फैली हुई है। बताया गया है कि यहां वाहनों की फिटनेस जांच में भी जमकर धन उगाही होती है। फिटनेस बनवाने की आस लिए लिए परिवहन कार्यालय आने वाले वाहन स्वामियों को अपनी जेबे ढीली करनी पड़ रही है। ऐसा भी नहीं कि जिन वाहनों की कंडीशन बेहतर है तो उन्हें फिटनेस के लिए चढ़ोत्री नहीं चढ़ानी पड़ती, परिवहन अधिकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाहन चाहे पुराना हो या नया, फिटनेस बनवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। परिवहन कार्यालय में जारी इस प्रकार की मनमानी से वाहन स्वामियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अर्थात् परिवहन कार्यालय में इन दिनों ड्राइविंग

लायसेंस बनवाने से लेकर फिटनेस आदि मे रिश्तत के तौर पर जमकर लूट की जा रही है। कार्यालयों में तैनात पटल कर्मचारी बाबू अपने एजेंटों के माध्यम से लाइसेंस बनवाने वाले अभ्यर्थियों और फिटनेस जांच कराने वाले वाहन स्वामियों को अपने झांसे में लेते हैं। पांच से दस हजार रुपये लेकर लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इस सिस्टम में पटल कर्मचारी और उनके एजेंट ही नहीं बल्कि आफसर भी शामिल हैं। जिनके टेबल तक सुविधा शुल्क का कमीशन पहुंचता है। जानकारों के अनुसार वाहन प्राइवेट बसें, स्कूल बसें, ट्रक हो या जीप और टैक्सी। सड़कों पर दौड़ने वाली व्यावसायिक गाडियों कागजों में तो फिट रहती हैं लेकिन अधिकतर का न लाइट सही होता है और न इंजन। सड़कों पर धुआं देती हुई चलने वाली इन गाडियों में परावर्ती टेप तक नहीं लगा होता है। यह तब है जब सरकार वाहनों

के फिटनेस को लेकर बेहद सतर्क है। अब तो अपनी आयु पूरी करने वाले वाहनों को स्क्रेप कबाड़ घोषित करने की योजना शुरू हो गई है। लेकिन परिवहन विभाग की मनमानी शासन के दिशा-निर्देशों पर भारी पड़ रही है।

वाहनों को देखने की जहमत भी नहीं उठाते

बता दें कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन के फिटनेस आदि के लिए रिश्तत के तौर पर रकम दे दी जाती है, उनकी फिटनेस देखने की परिवहन अधिकारी कर्मचारी जहमत तक नहीं उठाते। अर्थात् वाहन को बिना देखे ही उनके प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। इसका फायदा वो वाहन स्वामी उठा रहे हैं जिनके वाहन कंडम होने के चलते सड़क पर चलने लायक नहीं हैं। आये दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे परिवहन विभाग की लापरवाही प्रमुख मानी जा रही है।

फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए होती है इनकी जांच

जानकारों की मानें तो वाहन फिटनेस गाड़ी का इंजन, हार्न, आगे और पीछे की लाइट व इंडीकेटर, सीट, फाग लाइट, फस्टेड बाक्स, रिफ्लेक्टर, सफाई, डेंट-पेंट तथा नंबर प्लेट आदि की जांच होती है। लेकिन यहां परिवहन अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा वाहनों की जांच नहीं की जाती। रिश्तत लेने के बाद सब कुछ ओके कर दिया जाता है।

ऐसे बनता है फिटनेस प्रमाण पत्र

व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के समय ही बनता है दो साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र। दो साल के बाद प्रत्येक वर्ष जांच के बाद एक वर्ष के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र बनता है। वहीं गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र बनाया जाता है।

आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

सीधी। सहायक मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन श्री ओमप्रकाश बागरी, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.08.2018 को ग्राम सजवानी थाना अमिलिया में अभियोक्त्री की मां ने इस आशय कि रिपोर्ट कि वह अमिलिया बाजार में मजदूरी करने आई थी उसकी लड़की घर पर थी। जब वह अमिलिया बाजार से करीबन 05 बजे शाम को वापस घर गई तो देखी कि उसकी लड़की घर पर नहीं थी तब वह अपने बच्चों से पूछी की अभियोक्त्री कहाँ गई तब उसके बच्चे ने बताया कि वह कोदौरा बाजार गई है। रात तक जब अभियोक्त्री घर नहीं आयी तब वह आस पड़ोस रिश्तेदारी में पता तलाश की, तो कोई पता नहीं चला।

कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था। फरियादी की उक्त शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना अमिलिया के अपराध क्रं. 234/2019 अंतर्गत धारा 363 भा.द.सं. का गुमशुदा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री धान लगाने के लिए अपनी सहेली के साथ खेत में गई थी, जहां उसे अभियुक्त निवासी गजरहा मिला था, जिसे अभियोक्त्री डेढ़ वर्ष पूर्व से जानती थी। अभियुक्त अभियोक्त्री को अपने साथ लेकर

चितरंगी चला गया था। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 1086/2019में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री गरूण कुमार कोल के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त आयु 21 वर्ष, निवासी- गजरहा, थाना बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)को 363 भा.द.सं.02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

चित्ररंगी चला गया था। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 1086/2019में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री गरूण कुमार कोल के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त आयु 21 वर्ष, निवासी- गजरहा, थाना बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)को 363 भा.द.सं.02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

लोगों की स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वावलंबी बनाने में जुटे मृगेन्द्र

सीधी। लोगों की स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वावलंबी बनाने में सीधी जिले के रघुनाथपुर निवासी मृगेन्द्र गौतम पूरी तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। बकौल मृगेन्द्र गौतम के वे करीब 5 वर्ष से आरसीएम से जुड़े हुए हैं। यह राइट, कान्सेप्ट मार्केटिंग है, जो कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तीकरण में कार्य करती है। आरसीएम से जुड़ने पर रायल्टी जैसी इनकम भी मिलती है। उनको वर्ष 2019 में आरसीएम के संबंध में जानकारी मिली जिसके बाद उन्होंने एक साल तक मन लगाकर पढ़ाई की और पूरी जानकारी हासिल किए।

विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक

सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि दिनांक 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान का संचालन खरीफ पूर्व किया जाना प्रस्तावित है, उक्त अभियान अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधानों, उन्नत कृषि/ उद्यानिकी /पशुपालन/मत्स्य/ कृषि अभियांत्रिकी की तकनीकियाँ एवं कृषकों द्वारा किये जा रहे नवाचारों इत्यादि के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं तकनीकी हस्तांतरण के लिए उक्त अभियान के अन्तर्गत प्रतिदिन ग्राम पंचायतों पर निर्धारित रूट चार्ट अनुसार अभियान का क्रियान्वित किया जाना है।

इस हेतु स्थानीय स्तर पर उक्त अभियान के कार्यक्रम में संबंधित ग्राम पंचायतों के मैदानी अमले (पंचायत सचिव/ रोजगार सहायक/ कोटवार) को

निर्धारित स्थान एवं दिनांक को उपस्थिति के लिए आदेशित किया गया है।

उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, सहायक संचालक मत्स्य, सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड को निर्देशित किया है कि अपने स्तर से अपने-अपने विकास खण्डों में निर्धारित रूट चार्ट एवं निर्धारित प्रपत्र अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के मैदानी अमलों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अभियान के नोडल कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सीधी एवं कृषि विज्ञान केन्द्र जिला सीधी अनिवार्य रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी जिला-सीधी (म0प्र0)

पत्र क्र0.853/भू-अर्जन/प्रवा./2024/

सीधी दिनांक 20/05/2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रयनीति आदेश एफ 12-2/2014/सत/2ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 के अन्तर्गत निजी भूमि का शासकीय प्रयोजन हेतु क्रय किए जाने हेतु विचार किया जा रहा है जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है। भूमियों के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 04/06/2025 तक कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सीधी में आधार सहित प्रस्तुत करें। नियत दिनांक 04/06/2025 तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जावेगी।

भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	आराजी नं.	रकबा हे.	भू-धारक का नाम व पता	राज्य शासन के विभाग उपक्रम का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सीधी	बहरी	खैरा	388	0.0600	शिवप्रताप सिंह पिता नोखेलाल सिंह बाबूलाल सिंह पिता नोखेलाल अम्बिकेश सिंह पिता नोखेलाल सिंह रामपाल सिंह पिता नोखेलाल सिंह	कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म.प्र.)	बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु
			419/1	0.0400	छोटारकस पिता अकबर		
		योग	2 किता	0.1000 Ha.			

(एम.के. परते)

कार्यपालन यंत्री

जी-13223/25

लो.नि.वि. संभाग सीधी (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, म.प्र. लोक निर्माण विभाग, (म./स.) सीधी संभाग सीधी Website - www.mppwd.gov.in/pwdmp , email - eeppwdsidhi@mp.nic.in नि सू क्र. 04/2025-26					
निविदा आमंत्रण सूचना					
न्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्न कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा समस्त संसोधनों सहित के आधार पर, प्रपत्र - 'अ' में निविदाकारों, जो केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत हों, से आमंत्रित की जाती है :-					
युघ क्र.	टेंडर आईडी01	कार्य का नाम	टेंडे की अनुमानित राशि (₹ लाख में)	1.. अमानत राशि 2. नि. प्रपत्र का मूल्य	1.निविदा क्रमांक 2. कार्यवधि
1	2	3	4	5	6
1	2025 PWDRB_422299	उपसंगम सीधी के अन्तर्गत बारी पनियरा मार्ग में पैच नरमत्त का कार्य (अनुबंध क्र. 42 वर्ष 2018-19 दिनांक 08.08.2018 के परकारनेस गारंटी अन्तर्गत) लोडिंग, सड़क एस्.ओ.आर. 11.04.2025	10.87	1.21740 2.2000	1. प्रथम आमंत्रण 2 02 माह
योग :-			10.87		
1. ऑन लाइन पोर्टल http://mptenders.gov.in के माध्यम से निविदा प्रपत्र क्रय करने, डाउनलोड एवं निविदा डालने का समय एवं दिनांक 27.05.2025 सुबह 10.30 से 09.06.2025 शाम 5.30 तक है। 2. अमानत राशि, केन्द्रीयकृत पी.डब्ल्यू.डी. पंजीयन, शपथ पत्र, जी.एस.टी.एन. एवं अन्य अभिलेख (सिफाफा-अ), सिर्फ ऑनलाइन अपलोड किये जा सकते हैं। 3. निविदा से संघटित सशोधन, समय परिवर्तन आदि की सूचना केवल वेबसाइट के माध्यम से दी जावेगी। 4. कितनी निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है।					
(एम.के. परते) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग सीधी (म.प्र.)					
जी-13224/25					



संपादकीय

पाकिस्तान के लिए जासूसी

भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही एक महिला की गिरफ्तारी चिंता का विषय है। पाकिस्तान की करतूतें किसी से छिपी नहीं हैं। आतंकवादियों को पालने और सीमा पर तनाव बढ़ाने के साथ एक के बाद एक वह साजिशें रचता रहा है। इसमें वह भारतीय नागरिकों को बहला-फुसला या किसी तरह फंसा कर खुफिया जानकारीयां जुटाने का प्रयास करता रहा है। बीते कुछ दशक में उसने अपना यह जासूसी संसल मजबूत कर लिया है।'आपरेशन सिंदूर' के बाद चलाए गए विशेष अभियान के तहत जिस तरह एक के बाद एक पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि उसका संचाल काफ़ी फैला हुआ है। पर सवाल यह भी उठता है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की जो सतर्कता अब दिखाई दे रही है, वह पहले क्यों नहीं थी। हरियाणा की यूयूअर ज्योति मल्होत्रा को दुश्मन देश की खुफिया एजेंसियां 'अपने संपर्क' के तौर पर काफी समय से तैयार कर रही थी।हरानी है कि इसकी भनक भारतीय एजेंसियों को इतनी देर से क्यों लगी? इसके अलावा कई भारतीयों का इण्डएसआइ के संपर्क में आना गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है। एनआइए ने कैथल में एक पाक जासूस को पकड़ा, तो पंजाब पुलिस ने सैन्य जानकारी साझा कर रहे गुरदासपुर के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब तो जासूसी की जांच उत्तर प्रदेश के रामपुर तक जा पहुंची है।ऐसा लगता है कि पहलगाम आतंकी हमले के पहले से पाकिस्तान, भारत में जासूसों का जाल बना रहा था। अगर वह ऐसा कर रहा था, तो इस कड़ी को पकड़ने में चूक कैसे हुई। अगर यह दावा किया जा रहा है कि आतंकी हमले से पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई थी, तो यह निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इसकी तह में जाने की जरूरत है। कुछ जासूसों का राजनीतिक संपर्क भी देखा गया है।डोआरडीओ के एक वैज्ञानिक की गिरफ्तारी को लोग आज भी नहीं भूलें हैं। तब उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल भी उठा था। जासूसों को बीजा कौन और कैसे दिलवाता है, इसकी जांच भी होनी ही चाहिए।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जहां दुनिया के देशों में टुकड़ो-टुकड़ों में काम हो रहा है वहीं आंध्रप्रदेश की नई राजधानी अमरावती को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से संचालित शहर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने काम भी शुरू कर दिया है । अमरावती को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से संचालित शहर बनाने में करीब करीब 65 हजार करोड़ रुपए की लागत आयेगी और सोलर, पवन और जल विद्युत पर आधारित इस परियोजना में अमरावती में उपयोग आने वाली सारी बिजली रिन्यूवल एनर्जी स्रोत से ही प्राप्त होगी।

अमरावती मॉडल देगा दुनिया के देशों को नई दिशा

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)

अमरावती को पूरी तरह से ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में जो कार्य आरंभ हो रहा है वह समूची दुनिया के लिए एक मिसाल है। वहां पर सरकारी भवनों के साथ ही अन्य स्थानों पर सोलर पेनल और पवन उर्जा के स्रोत लगाये जाएंगे। पनबिजली परियोजना का संचालन होगा।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जहां दुनिया के देशों में टुकड़ी-टुकड़ों में काम हो रहा है वहीं आंध्रप्रदेश की नई राजधानी अमरावती को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से संचालित शहर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू ने काम भी शुरू कर दिया है। अमरावती को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से संचालित शहर बनाने में करीब करीब 65 हजार करोड़ रुपए की लागत आयेगी और सोलर, पवन और जल विद्युत पर आधारित इस परियोजना में अमरावती में उपयोग आने वाली सारी बिजली रिन्यूवल एनर्जी स्रोत से ही प्राप्त होगी। सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली जीवाश्म ऊर्जा का अमरावती में नामोनिशान नहीं होगा। अपने आप में यह दुनिया के लिए ग्रीन एनर्जी के सपने को अमली जामा पहनाने की बड़ी, महत्वाकांक्षी और दुनिया के देशों के लिए प्रेरणीय पहल मानी जानी चाहिए। कोई इसे इतिहास रचने की बात करता है तो कोई ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी और रचनात्मक पहल के रूप में देख रहे हैं। कहा जाए तो दुनिया के देश जिस तरह से ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बड़े बड़े शिखर सम्मेलनों के साझा घोषणा पत्रों में घोषणाएं होती है उससे अलग हटकर आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू की इस पहल को माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इस परियोजना की आधारशिला रखने जा रहे हैं। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र की नई राजधानी की आधारशिला रखी जाएगी तो ग्रीन एनर्जी का यह प्रोजेक्ट 217 वर्गमीटर को समायें हुए होगा। अमरावती को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी युक्त दुनिया का पहला शहर बनाने के लिए 2050 तक की मांग का आकलन कर लिया गया है करीब 2700 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। इसमें स 30 प्रतिशत सोलर और पवन आधारित उर्जा होगी

तो 70 प्रतिशत बिजली का उत्पादन पनबिजली आधारित होगी।

ग्रीन एनर्जी के चार प्रमुख स्रोत है। इसमें सूर्य की गर्मी आधारित सोलर ऊर्जा, हवा के झोंकों पर आधारित पवन ऊर्जा, जल आधारित पन बिजली परियोजना और भूगर्भ के ताप आधारित भूतापीय ऊर्जा को रिन्यूवल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुखता से सोलर, पवन और पन बिजली को लिया जाता है। दरअसल जीवाश्म आधारित उर्जा जिसमें



प्रमुखतः कोयला व लिग्नाइट का प्रयोग होता है उसके चलते जलवायु में तेजी से परिवर्तन हुआ है और आज दुनिया के देश तापमान वृद्धि को 1.5 प्रतिशत तक रखने के लिए जुड़ रहे हैं। 2 प्रतिषत वृद्धि दर को डेढ़ प्रतिशत लाना टेड़ी खीर बना हुआ है। पेरिस घोषणा के अनुसार दुनिया के देशों को इसकी जिम्मेदारी सीपी गई है अन्यथा जलवायु परिवर्तन के जिस तरह के परिणाम हम आये दिन देखने लगे हैं जिसमें तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेशियरों का सिकुड़ना, अनर्पेक्षित मौसम चक्र कभी तेज गर्मी तो कभी तेज सर्दी और कभी तेज बरसात। आंधी तूफान, जंगलों में दवानल, तूफानों चक्रवातों के नए नए रूप और बार

बार आवृति हमारे सामने हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र किनारे के शहरों के सामने अस्तित्व का संकट आ गया है तो जंगलों के दवानलों का असर आसपास के शहरों खासतौर से अमेरिकी शहरों में देखा जा चुका है। सूखा और बाढ़ आम होती जा रही है तो दवाओं के बेअसर होने और संक्रामक रोगों की बढ़ोतरी सामने हैं। दुनिया के देश खासतौर से मौसम विज्ञानी इन हालातों को लेकर चिंतित है और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को सीमित

करने के उपायों को लेकर प्रयासरत है। हालांकि इसमें सरकारों की ईच्छा शक्ति, संसाधन, आर्थिक सामाजिक हालात के साथ ही विकसित देशों द्वारा खुले दिल से सहयोग नहीं करना बड़ा कारण बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के संकट से दुनिया के देश सावचेत नहीं हो। बल्कि इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों को लेकर रैंकिंग भी जारी होने लगी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन रैंकिंग में भारत दसवें स्थान पर है हालांकि यह इससे पहले के साल की तुलना में रैंकिंग पिछड़ी है। मजे की बात यह है कि हालिया सूचकांक के विश्लेषण से साफ हो जाता है कि आज

भी इस सूचकांक को एक से तीन नंबर की रैंकिंग वाले देश की प्रतीक्षा है। रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर है और उसका चौथे स्थान है। नीदरलैंड, इंग्लैण्ड, फिलिपिन्स, मोरक्को, नार्वे क्रमशः है तो भारत दसवें स्थान पर है। देश में रिन्यूवल एनर्जी की दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं। गुजरात के कांडला सेज को पूरी तरह से हरित औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम के शोर मंदिर को ग्रीन एनर्जी पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान मिल चुकी है। डेनमार्क का कोपेन्हेगेन भी इसी श्रेणी में आता है। आस्ट्रेलिया का एडिलेड, कोरिया का सियोल, आइवकोस्ट का कोकोडी, स्वीडन का माल्मो और दक्षिणी अफ्रिका का केपटाउन ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ते हुए शहरों में से हैं। गुजरात के कांडला सेज में 1000 एकड में साढ़े तीन लाख पेड़ लगाया गया है। समुद्र के नमक के पानी से प्रभावित क्षेत्र को जलवायु की दृष्टि से करीब करीब बदल ही दिया गया है।

अमरावती को पूरी तरह से ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में जो कार्य आरंभ हो रहा है वह समूची दुनिया के लिए एक मिसाल है। वहां पर सरकारी भवनों के साथ ही अन्य स्थानों पर सोलर पेनल और पवन उर्जा के स्रोत लगाये जाएंगे। पनबिजली परियोजना का संचालन होगा। पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का ही उपयोग होगा। हालांकि यह अपने आप में चुनौतीभरा काम होगा पर ईच्छा शक्ति और कुछ नया करने की भावना से आगे बढ़ा जाता है तो फिर कोई कार्य असंभव नहीं होता है। हालांकि केन्द्र व राज्य सरकारें अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। राजस्थान रिन्यूवल एनर्जी उत्पादन के क्षेत्र में समूचे देश में आगे है और भड़ला पार्क जैसे सोलर पार्क यहां विकसित हो चुके हैं। सरकार अब घरों की छतों पर सोलर एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है तो खेती में सोलर पंपों और अन्य कार्यों में उपयोग सकारात्मक प्रयास माने जा सकते हैं। पर अमरावती इन सबसे अलग इसलिए हो जाती है कि यहां समग्रता से प्रयास करते हुए समूचे शहर को ग्रीन एनर्जी युक्त बनाया जा रहा है यह सराहनीय होने के साथ ही प्रेरक भी है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

बांग्लादेश को 6415 करोड़ का इटका तकि यूनुस सरकार का दिमागी बैलेस ठीक रहे

रामस्वरूप रावतसरे
भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई उत्पादों पर पाबंदियां लगाई है। इससे बांग्लादेश को करीब 770 मिलियन डॉलर (करीब 6415 करोड़ रुपए) का आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बांग्लादेश के गार्ममेंट और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स के उद्योग पर पड़ेगा। इस्लामी सरकार के नेतृत्व में गंभीर आर्थिक चुनौतियों और आंतरिक अस्थिरता से जुड़ रहे बांग्लादेश के लिए यह किसी इटके से कम नहीं है।

बिजनेस थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनशिएटिव (जीटीआरआई) की 18 मई 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट में भारत की ओर से लगाई गई पाबंदियों से बांग्लादेश को यह नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। यह उसके कुल आयात का करीब 42 प्रतिषत है। इन पाबंदियों के तहत कई उत्पादों का कारोबार अब सड़क मार्ग की जगह केवल निश्चित किए बंदरगाहों तक सीमित कर दिया गया है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के निर्देश पर 18 मई 2025 से बांग्लादेश से आयातित कई श्रेणियों के सामानों पर तत्काल बंदरगाह प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इस निर्णय के तहत प्रमुख वस्तुएँ जैसे वस्त्र, तैयार खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक और पीवीसी उत्पाद और

लकड़ी का फर्नीचर अब केवल चुनिंदा समुद्री बंदरगाहों से ही भारत में आ सकेगे जबकि भूमि मार्गों से इनका आयात पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नई नीति के अनुसार, बांग्लादेश से आने वाले कपड़े जो करीब 618 मिलियन डॉलर (करीब 5130 करोड़ रुपए) के होते हैं, अब केवल दो बंदरगाहों के जरिए ही भारत में लाए जा सकेंगे। इनके सड़क मार्ग से आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह की पाबंदी फूड प्रोसेस्ड आयटम्स, फ्लैट ड्रिक्स, कार्बोनेटेड ड्रिक्स, कपास और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों पर भी लगाई गई है।

जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश से रेडीमेड गार्ममेंट्स का आयात अब किसी भी सड़क मार्ग से नहीं होगा। इनका आयात अब केवल मुंबई के न्हावा शेवा और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों से ही होगा। इसके अतिरिक्त असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के किसी भी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस)/एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी), तथा पश्चिम बंगाल में चंगराबांधा और फुलबारी के एलसीएस के माध्यम से फ्लैट्स ड्रिंक, कार्बोनेटेड पेय,

बेकड सामान, शैक्स, चिप्स, कम्फेक्शनरी, कपास और सूती धागे, प्लास्टिक, पीवीसी और लकड़ी का फर्नीचर आयात करने पर पाबंदी लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय कपड़ा निर्माता लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि

बांग्लादेशी प्रतिस्पर्धियों को अनुचित लाभ मिल रहा है। उन्हें चीन से बिना शुल्क के कपड़ा आयात और सरकारी नियंत्रित सॉफ्टिडी का फायदा मिलता है जिससे वे भारतीय बाजार में 10-15 प्रतिषत तक सीमा दोरी पर सामान बेच पाते हैं।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनशिएटिव (जीटीआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने नई पाबंदी इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर लगाए हैं। ये प्रतिबंध चीन की ओर बांग्लादेश के बढ़ते कूटनीतिक झुकाव के प्रति भारत की प्रतिक्रिया भी है। इस साल फरवरी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कपड़ा मंत्रालय के बजट में 19 प्रतिशत

की वृद्धि की थी जिससे उद्योग को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है। वित्त वर्ष 2024-25 के 4417.03 करोड़ रुपए की तुलना में अब मंत्रालय की 5272 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय कपास मिशन शुरू करने की घोषणा भी की है। पूर्व में बांग्लादेश कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था लेकिन वहीं का कपड़ा क्षेत्र इस समय वित्तीय संकट, बिजली की कमी और बढ़ती हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद स्थिति और अधिक खराब हो गई है। इस पृष्ठभूमि में भारत के पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली और नीदरलैंड जैसे प्रमुख बाजारों में कपास और वस्त्र निर्यात बढ़ाने का मौका है। ऐसे में भारत उन सभी रणनीतिक कदमों को अपना रहा है जिनसे बांग्लादेश से हट रहे वैश्विक व्यापार को अपनी तरफ किया जा सके। भारत द्वारा बांग्लादेशी सामानों पर पाबंदी लगाने के फैसले को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की विवादस्पद टिप्पणी की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। चीन में दिए गए एक भाषण के दौरान यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉकड बताते हुए बांग्लादेश को समंदर का इकलौता गार्जियन बताया था।

वर्ग पहली 5739

1		2	3	4	5	6
			7		8	
9	10		11			
12					13	
			14		15	
	16			17		
18			19		20	21
		22		23		

संकेत: बाएं से दाएं

- भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार (8)
- ताकत सहित, बलवान, ताकतवर (3)
- आपस में गुंथी एवं फैली हुई चीजों का विस्तार (2)
- निहा, दो की संख्या, मृत्युदेव (2)
- रिपेट का अपभ्रंश, किससलूट (3)
- सिख संप्रदाय के आदि गुरु (3)
- एक दिग्गत हास्य अभिनेता जिन्होंने (1937 से 1989 के बीच 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया) (2)
- युद्ध, लड़ाई, रण, संग्राम (3)
- विशाल भूभाग में फैलाना (4)
- इंद्रधनुष में रंगों की संख्या (2)
- नतीला, परिणाम, सुख-दुख का भोग (2)
- जलील अंश, शोखा (2)
- आहुति के रूप में दिया हुआ (2)
- कार्यान्वय, ऑफिस (3)

ऊपर से नीचे
1. सुलोचना, सुंदर नेत्रों वाली (4)
2. अर्निट का डर या खौफ, कूट (2)
3. संख्या मृगक अंक, अदर, संख्या (3)
4. गिरोह का मुखिया (4)

- पांच उंगलियों सहित इथेली का अंगुल भाग (2)
- छायाछिमांड, इच्छा रखने वाला (5)
- मन के अनुसार, मन के अनुकूल (5)
- आने-जाने का भाग या क्रिया (5)
- शिष्टता, नस्लान, यह धर्मर के साथ हेमामालीनी की पहली फिल्म थी (4)
- कमल, लोहे का अर्द्धचंद्राकार टुकड़ा, कुमुद आदि फूलों की लंबी व खोखली नली या डंडी (2)
- परस्पर साध रहने वाला व्यक्ति, मित्र, सखा (2)
- महाशय या श्रीमान का अंग्रेजी में यह कहते हैं (2)
- मित्र का नीचे का अंक, प्रत्येक (2)
- बुनियाद, नींव, जड़ (2)

वर्ग पहली 5738 का हल

म	ई		ग	घ	आ
ह		म	ड	र	ज
ज	न	क	क	ना	ग
	दा	स	ती		वा
ना	र	द	स	म	क्ष
जु		अ	त	ल	कु
क	ह	र	वा	म	मु
ता	र	म	स	ल	

देश के आइकन्स को ट्रोल करने की यह कैसी सोच?

राजीव खंडेलवाल

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एक नागरिक को ‘‘जीत के अधिकार’’ प्रदान करता है। उस अधिकार में ‘‘मानवीय गरिमा’’ के साथ मनुष्य के जीवन का सार्थक, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाने वाले समस्त पहलू शामिल हैं। अतः देश का संविधान निःसंदेह प्रत्येक नागरिक को ‘‘सम्मान से जीने का अधिकार’’ देता है, जिसकी रक्षा का दायित्व कार्यपालिका व न्यायपालिका पर है। फलतः संविधान किसी भी व्यक्ति को एक नागरिक के सम्मान पर जाति, धर्म के आधार पर चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है। यह सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों के जीने अधिकार की रक्षा कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने देने की परिस्थितियां निर्मित सुनिश्चित करे। तदनुसार प्रत्येक नागरिक को ‘‘असम्मान के कटपत्र के घेरे से सुरक्षा प्रदान करे।’’ हालांकि ‘‘खलक का हलक किसी ने बंद नहीं किया है’’ लेकिन जो देश के ‘‘फलक’’ पर गंदी इबारतें लिख उसका सम्मान घटाये, उसे संविधान की ‘‘हड्क’’ दिखानी भी जरूरी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, शहीद नरवाल की विवाह हिमांशी नरवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. माद्री काकोटी, भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर जैसे ‘‘आइकॉन’’ व प्रतिष्ठित नागरिकों हो, जिनकी वेशमी से साइ सोशल मीडिया पर निम्न से निम्नतम स्तर पर जाकर वास्तविक हनन करके बेरोक-टोक टोल किया जा रहा हो और सरकार है कि ‘‘खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बेटे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं’’ की मुद्रा में हाथ पर हाथ धरी

बैठी हुई है। जिस प्रकार चुप रहना ‘‘सहमति’’ मानी जाती है, जिसे कहते हैं ‘‘खामोशी नीम रजा’’, उसी प्रकार ‘‘कुछ कार्रवाई न करना’’ भी क्या उत ट्रोलिंग टीम के लिए सरकारी की ‘‘सहमति’’ मानी जाए? यानी कि ‘‘सैया भए कोतवाल तो फिर’’। संघर्ष विराम का निर्णय सरकार का! फिर सेना व सरकार के अधिकारियों को ट्रोल क्यों। आइये! कुछ प्रकरणों का अध्ययन करें व स्थिति समझने का प्रयास करें। ‘‘ऑपरेशन सिंदूर’’ के प्रारंभ होने ही संघर्ष विराम तक सेना की लगातार तीन दिन व उसके बाद भी ‘‘प्रेस ब्रीफिंग’’ विदेश सचिव विक्रम मिशरी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, नपुलेश शर्मा में प्रभावी रूप से कर रही थी। भारत सरकार इस टीम को सामने लाकर देश की सांप्रदायिक झड़पना की भंग करने के पाकिस्तान के कुरिस्त प्रयासों के जवाब का एक ‘‘सांकेतिक संदेश’’ भी सफलतापूर्वक दे रही थी। इस देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर खूब सराहा भी गया। परन्तु अचानक भारतीय सेना की जीत की अवस्था, स्थिति के समय पर अप्रत्याशित ‘‘संघर्ष विराम’’ की घोषणा होने के कुछ समय पश्चात ही शोशल मीडिया पर विदेश सचिव विक्रम मिशरी व कर्नल सोफिया को अपमानित कर बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा। जबकि वस्तुतः ये संघर्ष विराम की जानकारी देते समय विराम तक सेना का एक अंग होकर मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे थे। ‘‘संघर्ष विराम’’ का निर्णय विदेश सचिव या कर्नल सोफिया कुरैशी या सेना के स्तर पर न होकर राजनीतिक स्तर पर हुआ था।

आज का राशिफल



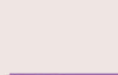
मेष

आज दिन करियर और वित्तीय दृष्टि से अत्यंत अनुकूल है। आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे पदोन्नति के द्वार खुलेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें किसी महत्वपूर्ण सौदे से लाभ होने की संभावना है। रुके हुए सरकारी या कानूनी कार्यों में भी सफलता मिलेगी।



मिथुन

आज दिन मिश्रित फलदायक है। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी और सहयोगियों से असहमति हो सकती है। बिजनेस में आंचाक कोई निर्णय लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।



सिंह

आज अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा। आपके विरोधी सक्रिय हैं और आपको छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कोई निर्णय लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।



वृष

आज मेहनत का भरपूर फल मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको छवि मजबूत होगी और किसी महत्वपूर्ण परियोजना में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। व्यापार में आज साझेदारी से अच्छा मुनाफा होगा।



कर्क

आज दिन आर्थिक तरक्की और करियर में उन्नति का संकेत दे रहा है। जब में कार्यभार बढ़ सकता है लेकिन आपके प्रदर्शन की तारीफ होगी। जो लोग विदेश से जुड़े व्यवसाय में हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है।



कन्या

आज दिन प्रगति का है। पुराने अधूरे काम पूरे होंगे और नए प्रॉजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। कला, लेखन, मीडिया या अकादमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। फ्रीलान्सिंग या दूरस्थ कार्यों में धन की प्राप्ति के योग है।



तुला

आज दिन आर्थिक रूप से बेहतर साबित हो सकता है, बशर्ते आप जोखिमों का आकलन करें। कुछ पुराने निवेश लाभ दे सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ अधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहारिक रवैया स्थिति को नियंत्रित करेगा।



धनु

आज दिन रणनीतिक फैसलों के लिए श्रेष्ठ है। आपकी लीडरशिप क्षमता निखरकर सामने आएगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं। विशेषकर व्यापारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं।



कुंभ

आज दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र में बकवर्को वे आपको बेवजह के कार्यों में उलझा सकते हैं। उच्चाधिकारियों से संवाद में पारदर्शिता रखें। बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है लेकिन भुगतान में देर संभव है। यात्रा से लाभ हो सकता है। धेरू खर्च बढ़ने के योग है, अतः बजट का ध्यान रखें।



वृश्चिक

आज अपने कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना होगा। ऑफिस में किसी प्रॉजेक्ट में आपकी भूमिका अहम रहेगी, पर तनाव भी रहेगा। बिजनेस में फंडिंग या कर्ज से संबंधित कोई निर्णय लेना पड़ सकता है।



मकर

आज दिन व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा होगा। कार्यस्थल पर आपकी योग्यता की परीक्षा हो सकती है। अतिरिक्त कार्यभार या किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति के कारण आपका दिन काफी व्यस्त रहेगा। हालांकि इससे आपकी नेतृत्व क्षमता को सराहा जाएगा।



मीन

आज दिन करियर और आर्थिक रूप से उन्नतिदायक है। व्यापार में विस्तार की योजना आज मूर्त रूप ले सकती है। नौकरी में प्रमोशन या इनक्रीमेंट की संभावना बन रही है। रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

संक्षिप्त समाचार

हिमाचल प्रदेश में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का खतरा, सूअरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध



शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग ने राज्य में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद सूअरों की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। हाल ही में बिलासपुर के झंडूता उपमंडल की कोलका पंचायत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से संक्रमण का मामला सामने आने के बाद ये आदेश जारी किए गए। इस संक्रमण के कारण एक सूअर पालन केंद्र में 36 सूअरों की मौत हो गई थी जबकि चार को विभाग ने नियमानुसार मार दिया था। पशुपालन विभाग ने सूअर पालन केंद्र को खाली करारक सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी ने बताया कि पशु औषधालय दसलेहय के अंतर्गत आने वाले इस फार्म में कुल 40 सूअर पाले गए थे।

केंद्रीय मंत्री आठवले ने पीओके को वापस लेने के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया

मुंबई, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सरकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को वापस लेने के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू करने की बुधवार को मांग की और इस बात पर बल दिया कि कूटनीतिक प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि पीओके को भारतीय नियंत्रण में वापस लाया जाना चाहिए। आठवले ने कहा कि सात मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाइ को रोकना एक सही कदम नहीं था। उन्होंने कहा, "सैन्य कार्रवाई को रोकना अच्छी बात नहीं थी। आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई बंद नहीं हुई है। हमारे रक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' (आठवले) के प्रमुख ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम शहर में हुए आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार की त्वरित जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की।

दुष्कर्म के मामलों में तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा

बहराइच, एजेंसी। बहराइच और श्रावस्ती जिलों की विशेष अदालतों ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में आरोपी तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। बहराइच जिले में विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-को बताया कि 19 जनवरी 2018 को कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय बालिका को लाले उर्फ राकेश यादव तथा कल्लू उर्फ रामराज यादव बहला फुसलाकर ले गए और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाले व कल्लू को 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उधर, श्रावस्ती जिले में ऐसे ही एक मामले में पांच वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए पाक्सो अदालत ने बुधवार को 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के. पी. सिंह ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी के साथ थाना क्षेत्र के सौरपुर गांव के निवासी ओमकार पासवान ने 29 जुलाई 2020 की रात दुष्कर्म किया था। इस घटना से क्षुब्ध पीड़िता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पीड़िता (मृतका) की मां की तहरीर पर 30 जुलाई 2020 को इकौना थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

गहलोत बोले-हम जादूगर हैं, ट्रिक करते हैं... डोटासरा को बताया सियासी ट्रिक का हिस्सा!



जयपुर, एजेंसी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित राजीव गांधी पुण्यतिथि कार्यक्रम में अपने राजनीतिक अनुभवों, पार्टी में अपनी भूमिका और कांग्रेस के आंतरिक सियासी समीकरणों पर बेबाक टिप्पणी कर नई सियासी बहस छेड़ दी है। खास बात यह रही कि उन्होंने

एक बार फिर अपने 'जादू' वाले अंदाज में सियासी संकेतों की ट्रिक दिखाई - इस बार निशाने पर रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साल 2020 का पायलट खेमे का बगावत दौरे। गहलोत ने कहा, तीन बार मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात है। तीसरी बार तो आप जानते हैं... सरकार बच गई, वह तो चमत्कार ही था। यह तो

हाँकमान का आशीर्वाद और आपकी दुआओं से ही संभव हो सका। वरना पांच साल पूरे करने का सवाल ही नहीं था। डोटासरा भी उसी की देन हैं। उनके इस बयान को सीधे तौर पर 2020 में सचिन पायलट खेमे की बगावत और उसके बाद बने सियासी हालात से जोड़कर देखा जा रहा है, जब पायलट को डिटी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाकर डोटासरा को अध्यक्ष बनाया गया था।

राजनीतिक विश्लेषक इसे

गहलोत का एक

'मैसेज' मान रहे हैं

खासकर तब जब विधानसभा चुनाव हरने के बाद कांग्रेस राजस्थान में नए सिरे से समीकरण साध रही है। गहलोत के इस बयान को डोटासरा की भूमिका और उनके कद को फिर से 'री-डेफाइंग' करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत ने कहा, जितना मुझे मिला, उतना देश में बहुत कम नेताओं को मिला है। जब दिल्ली में नंबर एक और नंबर दो नेता

सरकार गिराने पर आमादा हो जाएं, तो सरकारें गिरती हैं - मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसके उदाहरण हैं। लेकिन राजस्थान में सरकार बच गई, वो चमत्कार था। इसके साथ ही उन्होंने 'जादू' की अपनी चर्चित छवि पर भी तर्जिया अंदाज में कहा, हम जादूगर हैं, हम ट्रिक करते हैं और लोग कहते हैं जादू हो गया। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) भी आज का जादू है। मैं खुद इसका खूब इस्तेमाल करता हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि इस चमत्कार को अपनाएं।

कार्यक्रम में गहलोत ने इंदिरा गांधी युग के नेताओं की स्थायी पकड़ और नई पीढ़ी की जरूरत पर भी बात करते हुए कहा, हमारी भी एक सीमा है। नई पीढ़ी आनी चाहिए, बदलाव जरूरी है। जो संभव है, वह हम कर रहे हैं। गहलोत की यह 'जादू भरी' टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में कई परतों वाली मानी जा रही है - जिसमें पुराने सियासी घात भी हैं, वर्तमान समीकरण भी और भविष्य की चाल भी।

ईडी के रडार पर कर्नाटक के गृहमंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब घर पर हुई छापेमारी

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर हैं। केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। एक दिन पहले ही गृहमंत्री से जुड़े शिक्षण संस्थाओं पर ईडी की टीम पहुंची थी। खबर है कि एक्स्टेरा रान्या राव के सोना तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी रेंज कर रही है। पीटीआई भाषा के अनुसार,



ईडी ने बुधवार को जी परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थाओं सहित कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी हवाला ऑपरेटर और अन्य ऑपरेटर को निशाना बनाकर की गई, जिन्होंने राव के खातों में कथित तौर पर

"फर्जी" वित्तीय लेनदेन किए थे। जांच एजेंसी ने कुछ महीने पहले राव के मामले सहित भारत में बड़े सोना तस्करी रैकेट के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की सहायता पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए मामला दर्ज किया था। ईडी सूत्रों ने

कहा कि एक शैक्षणिक ट्रस्ट पर संदेह है कि उसने कथित तौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के निर्देश पर राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया है। सूत्रों ने दावा किया कि ट्रस्ट परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और "प्रभावशाली" व्यक्ति राजनीतिक शस्त्रियत है। उन्होंने बताया कि तलाशी में पाया गया कि इस भुगतान (क्रेडिट कार्ड बिल के लिए) को "सत्यापित" करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिला।

राजस्थान में क्यों राजपूत बनाम जाट कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल इन दिनों खूब चर्चा में हैं। वजह है राजपूतों को लेकर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियां। पहले राजपूतों को लेकर बेटी वाली टिप्पणी और अब जाटों को सबसे बड़ा क्षत्रिय बताने वाले उनके बयानों के पीछे छिपी राजनीतिक वजहों की तलाश की जा रही है।

सांसद हनुमान बेनीवाल का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सांसद बेनीवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, उसके बाद यादव, फिर गुर्जर हैं। इसके बाद पटेल, पाटिल और मराठे आते हैं, फिर तुल्हार (राजपूतों का) नंबर आता है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो लड़ा है वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कोई शब्द नहीं, वर्ण है राजस्थान की राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं, लेकिन हाल ही में नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के एक बयान से समुदाय में हलचल सी पैदा हो गई है।

यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और इसके बाद राजपूत समाज में तीव्र आक्रोश देखने को मिला। राजपूत नेताओं और संगठनों ने इसे न सिर्फ एक जाति पर हमला, बल्कि संपूर्ण जातिगत अमान्यता का अपमान बताया। मारवाड़ राजपूत सभा भवन के सचिव केवी सिंह चांदरख ने इस बेनीवाल की राजनीतिक हताशा का परिणाम



बताया और चेतावनी दी कि सर्व समाज की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल का यह बयान यूं ही नहीं आया। यह 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए एक जातीय समीकरण गढ़ने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। जाट, यादव, गुर्जर, पटेल, पाटिल और मराठ-ये सभी सामाजिक रूप से प्रभावशाली जातियां हैं और विभिन्न क्षेत्रों में निर्णायक वोट बैंक भी मानी जाती हैं। बेनीवाल इन जातियों को एक बहुजन क्षत्रिय फ्रेम में जोड़कर गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस ध्रुवीकरण की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। राजस्थान में जाट और राजपूत दोनों ही समुदाय ऐतिहासिक रूप से

ताकतवर रहे हैं और कई बार एक-दूसरे के विरोध में आ खड़े हुए हैं। इस बयान से राजपूत समुदाय में गहरी नाराजगी फैलना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही यह राज्य के सामाजिक सौहार्द पर भी चोट करता है। कई राजपूत नेताओं ने इसे वीरभूमि का अपमान बताया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जनता पहले भी ऐसे बयानों का जवाब दे चुकी है और आगे भी देगी।

विश्लेषकों के मुताबिक, हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए नई सामाजिक गोलबंदी की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी आरएलपी को पिछले चुनावों में सीमित सफलता मिली थी, और अब वे खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसके आइटी सेल पर बेनीवाल द्वारा दूरी बढ़ाने का आरोप लगाया इस बात का संकेत है कि वह इस पूरे विवाद को पार्टी लाइन से ऊपर उठाकर जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से भुनाना चाहते हैं।

आखिरकार, यह कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान की राजनीति फिर उसी पुराने जातीय मोड़ पर लौट रही है, जहां बयानबाजी से न सिर्फ सामाजिक ताने-बाने को नुकसान होता है, बल्कि चुनावों का रुख भी तय होता है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है-समाधान की ओर या और गहराती खाई की ओर।

पीलीभीत में बाघ की दहशत, चार दिन में ली दो जान, पिंजरा लगाकर पकड़ने को जुटा वन विभाग



पीलीभीत, एजेंसी। यूपी के पीलीभीत में बाघ की दहशत फैल गई है। चतुर्षुत्र क्षेत्र में बाघ का वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में बाघ को लेकर दहशत बढ़ी है। वहीं वन विभाग बाघ को पकड़ने की कवायद में लगा है। बाघ को पकड़ने के लिए टीमें जुटी हैं। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और पिंजरा लगाकर बाघ को पकड़ने की कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि

सेहरामऊ क्षेत्र में चार दिनों में बाघ अब तक दो किसानों की जान ले चुका है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व समेत क्षेत्र की अन्य टीमों को भी बाघ को पकड़ने के लिए निगरानी और लोकेशन तलाशने के पकड़ने की कवायद में लगा है। बाघ को पकड़ने के लिए टीमें जुटी हैं। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और पिंजरा लगाकर बाघ को पकड़ने की कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि

रेंजर का घेराव : सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में बाघ को लेकर लगातार लापरवाही बरतने के मामले में ग्रामीणों का रेंजर के प्रति आक्रोश थम नहीं रहा है। बुधवार को जब रेंजर गांव में पहुंचे तो ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखकर रेंजर मौके से निकल गए। बाघ को पकड़ने के लिए मिली अनुमति के बाद पिंजरा लगा कर टीमें निगरानी में जुटी हुई हैं ताकि सही लोकेशन लेकर अधिकारियों को भेजा जा सके। थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव दुर्जनपुर और चतुर्षुत्र में चार दिनों के भीतर बाघ ने दो किसानों को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों की घटनाओं में खुदरा सामाजिक वानकी रेंज के रेंजर मनोज श्रीवास्तव मौके पर नहीं पहुंचे थे। मंगलवार को जब बाघ गन्ने के खेत में बीते दिवस दौड़ लगाते दिखे चुका है। वन विभाग बाघ की घेराबंदी कर उसको पकने की योजना बना रहा है।

से इंकार कर रही है। देर शाम ही बाघ घटना स्थल से महज सौ मीटर के दायरे में तेजराय के खेत में देखा गया था। वहां पर जाल को लगा दिया गया है। बुधवार को जबफिर से रेंजर गांव पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। ग्रामीणों ने घेराव किया तो रेंजर वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि रेंजर ने तहरीर दी है।

थाना सेहरामऊ उत्तरी के एसएसआई मनोज कुमार ने बताया कि घटनास्थल और बाघ की लोशन वाले स्थान पर पुलिस और वन विभाग की टीम लगी है। रेंजर से मारपीट की घटना नहीं हुई है। रेंजर की तरफ से कोई तहरीर भी नहीं दी गई है। संबंधित चतुर्षुत्र क्षेत्र में निगरानी में लगी टीमें को उस वक्त निगराई हुई कि जब हल्की बूंद पड़ी। जिससे निगरानी कार्य कुछ देर को प्रभावित हुआ। इस क्षेत्र में बार बार बाघ दिखने और उससे संबंधित वीडियो का शोर होता रहा। पर बाघ की सटीक लोकेशन वन कर्मियों व टीमों को नहीं मिली।

धुले जिले के दौरे के दौरान महाराष्ट्र विधानमंडल की समिति को रिश्तत देने का प्रयास हुआ: संजय राउत

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (उबाठा) के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धुले जिले के दौरे के दौरान राज्य विधानमंडल की प्राक्कलन समिति को 'रिश्तत' देने की कोशिश को नाकाम कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राउत ने बुधवार रात को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि धुले शहर में सरकारी अतिथि गृह के एक कमरे में पांच करोड़ रुपये से अधिक की नकदी मिली। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया, "जब विधानमंडल की प्राक्कलन समिति ने आज (बुधवार को) धुले जिले का दौरा किया तथा समिति को रिश्तत देने के लिए धुले के सरकारी विभाग गृह गुलमोहर के कमरा नंबर 102 में लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये रखे गए थे।" राउत ने कहा कि शिवसेना के पूर्व विधायक अनिल अन्ना गोटे और स्थानीय शिवसेना (उबाठा) नेताओं ने कमरे को बंद कर दिया और बाहर पहरा देने लगे। उन्होंने आरोप लगाया, "जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचित करने के बावजूद चार से पांच घंटे बीत गए और कोई नहीं आया... प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। रिश्तत का उद्देश्य विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और इसमें अधिकारियों की सल्लता को दबाना था।

कन्नड़ नहीं हिंदी में बात करूंगी, ऐसा कहने पर एसबीआई की महिला मैनेजर का ट्रांसफर



बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को अनेकल तालुक में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा प्रबंधक के कन्नड़ में बात करने से इनकार करने के व्यवहार की निंदा की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था, जिसमें कथित तौर पर एक ग्राहक के साथ वह कन्नड़ भाषा को लेकर बहस करती हुई सुनी जा सकती है। स्ख्हु ने महिला अधिकारी का ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। मंगलवार को सामने आए वीडियो में ग्राहक के साथ कथित बहस के दौरान, प्रबंधक को यह कहते हुए सुना जा सकता है: "मैं कन्नड़ में बिल्कुल बात नहीं करूंगी.....बल्कि हिंदी में बात करूंगी।" उन्हें बार-बार यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह कन्नड़ में बात नहीं करेंगी, जबकि ग्राहक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों का हवाला देते हुए दावा किया कि बैंक कर्मचारियों को क्षेत्रीय भाषा में संवाद करना आवश्यक है। इस घटना की

कन्नड़ कार्यकर्ताओं और कन्नड़ समर्थक समूहों ने कड़वी निंदा की। उन्होंने प्रबंधक द्वारा माफी मांगे जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर अपने पोस्ट में अधिकारी को स्थानांतरित करने की एसबीआई की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, "सूर्य नागर, अनेकल तालुक में एसबीआई शाखा प्रबंधक का कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करना और नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना, अत्यंत निंदनीय है। हम अधिकारी को स्थानांतरित करने की एसबीआई की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं। अब इस मामले को समाप्त माना जा सकता है।" हालांकि, सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए और सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए तथा स्थानीय भाषा में बात करने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने हैशटैग 'कन्नड़ फर्स्ट' के साथ लिखा, "मैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग से पूरे भारत में सभी बैंक कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक और भाषा संवेदीकरण प्रशिक्षण अनिवार्य करने का आग्रह करता हूं।" उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा का सम्मान करना लोगों का सम्मान करना है।

बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी प्रबंधक के बर्ताव की निंदा करते हुए कहा, "यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बैंकों को ग्राहकों की सेवा कन्नड़ में करनी चाहिए। सूर्या ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले ही लोक लेखा समिति (पीएस) की बैठक में उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसी भूमिकाओं के लिए स्थानीय भाषा में प्रवीणता अनिवार्य होने संबंधी कार्यालयीन अभिसूचना लागू करने के लिए कार्रवाई की

जाएगी। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि इसे उचित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। मैं एसबीआई के संबंधित अधिकारियों से डीएफएस की नीति को तत्काल लागू करने का आग्रह करता हूं जिसमें स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। मैंने संबंधित अधिकारियों से इस तरह का व्यवहार करने वाली प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है।" इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी टी वी मोहनदास पई ने कहा कि यह मुख्यमंत्री से पूरी तरह सहमत है और सभी ग्राहकों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "प्रत्येक राज्य या जिले में सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में बोलने का पूरा प्रयास करना चाहिए और स्थानीय नागरिकों के प्रति गरिमा और सम्मान प्रकट करना चाहिए। गैर-अंग्रेजी भाषी लोगों को कभी नीचा नहीं दिखाया जाए। स्थानीय भाषा की जगह हिंदी कोई स्वाभाविक भाषा नहीं है।"



हितग्राहियों का ई-केवाईसी सात दिनों में शत-प्रतिशत पूरा करें : कलेक्टर

रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी अपडेशन की विकासखण्डवार तथा समितिवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी समिति प्रबंधक उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन तथा उचित मूल्य दुकान चलाने वाले स्वसहायता समूह हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ई केवाईसी सात दिवस में कराएं। इसके लिए 24 मई को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो व्यक्ति पात्र पाए जाएं उनके ई केवाईसी दर्ज कराएं। विषमता परिवार, मृतक, डुप्लीकेट तथा अपात्र हितग्राहियों के नाम राशन मित्र पोर्टल से काटने की भी कार्यवाही करें। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक तथा सेल्समैन मिलकर



अपात्रों के नाम पोर्टल से 26 मई तक अनिवार्य रूप से पृथक कराएं। स्थाई रूप से पलायन करने वाले परिवारों के नाम भी पोर्टल से पृथक करें। जिले में एक जून से राशन वितरण की ऑनलाइन प्रणाली लागू की जा रही है। जिन हितग्राहियों का ई केवाईसी नहीं होगा उन्हें जून माह से राशन नहीं मिलेगा। इसलिए

सभी हितग्राहियों की ई केवाईसी सात दिनों में अनिवार्य रूप से कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अभी आप सबके पास सात दिनों का समय है। इसमें रात-दिन काम करके ई केवाईसी का लंबित कार्य पूरा करा लें। आर्वाटित खाद्यान्न का

हर माह वितरण 95 प्रतिशत से अधिक हो रहा है। इसलिए ई केवाईसी भी 95 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। अपात्र व्यक्तियों के नाम काटने की कार्यवाही तत्परता से करें। जून माह से स्मार्ट राशन प्रणाली लागू होने के बाद ई केवाईसी के अभाव में यदि हितग्राही खाद्यान्न से वंचित होते हैं तो सेल्समैन समिति प्रबंधक, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। अपात्रों को खाद्यान्न वितरण की वसूली की भी कार्यवाही की जा सकती है। कलेक्टर ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 24 मई को विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने ई केवाईसी में लापरवाही बरतने पर

उचित मूल्य दुकान अतैरला, लूक, पटेहरा के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। ई केवाईसी की मानीटरिंग में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने आजीविका मिशन के ब्लाक समन्वयक जवा को नोटिस देकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने समिति प्रबंधकों को आगामी दो माह तक ऋणों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने तथा बड़े बकायादारों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश तांडेकर, सहायक आपूर्ति अधिकारी सुभाष द्विवेदी, प्रभारी उपायुक्त सहकारिता, सभी सीएमओ, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समिति प्रबंधक तथा उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन उपस्थित रहे।

नरवाई जलाने वाले किसानों पर 141500 रुपए का जुर्माना

रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सम्पूर्ण रीवा जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि नरवाई जलाने वाले किसानों पर 141500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। तहसील ल्योंथर में 32500 रुपए, तहसील जवा में 35000 रुपए, तहसील सेमरिया में 47500 रुपए, तहसील सिरमौर में 25000 रुपए तथा तहसील गुढ़ में 1500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। तहसील हुजूर में एक किसान के विरुद्ध एफआईआर

दर्ज कराई गई है। तहसील रायपुर कर्चुलियान तथा मनगवां में भी नरवाई जलाने वाले किसानों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का समय सीमा पूरा होने पर इनके विरुद्ध भी जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर ने कहा है कि किसान किसी भी स्थिति में खेतों की नरवाई न जलाएं। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ-साथ आग लगने की भी खतरा रहता है। सभी तहसीलादार नरवाई जलाने की सूचना मिलने पर कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ जाकर पंचनामा बनाएं तथा नरवाई जलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

उद्योग विभाग की कार्यशाला 24 मई को

रीवा। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए आरएएमपी योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नवीन प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला 24 मई को आयोजित की जा रही है। इस संबंध में जिला महाप्रबंधक उद्योग ने बताया कि कार्यशाला स्टार होटल में शाम 6 बजे आरंभ होगी। कार्यशाला में मध्यप्रदेश की एमएसएमई डवलपमेंट पालिसी, एमएसएमई भू आवंटन नियम 2025 तथा एमपी स्टार्टअप पालिसी की जानकारी दी जाएगी। सभी आमंत्रितों से कार्यशाला में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

सभी पंचायतों में 24 मई को ई केवाईसी के लिए होगी विशेष ग्राम सभा

विशेष ग्राम सभा में ई केवाईसी कराएं तथा अपात्र के नाम काटें : कलेक्टर

रीवा। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ई केवाईसी की जा रही है। इसके लिए 24 मई शनिवार को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि ग्राम सभा आयोजन के लिए तत्काल सूचना जारी कर दें। निर्धारित तिथि में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कराकर उसमें उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन और समिति सेवक राशन कार्ड में दर्ज सभी व्यक्तियों की ई केवाईसी करा लें। ग्राम सभा में मृत हितग्राहियों, विषमता परिवार के सदस्यों और स्थाई रूप

से पलायन करने वाले सदस्यों की सूची का भी वाचन कर दें। इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव तथा रोजगार सहायक मृतक, डुप्लीकेट नाम तथा विषमता परिवार के सदस्यों के नाम राशन मित्र पोर्टल से पृथक करने की कार्यवाही करें। ई केवाईसी शत-प्रतिशत अपडेशन तथा अपात्रों के नाम काटने की कार्यवाही 26 मई तक पूरी करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

कलेक्टर ने कहा है कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम सभाओं के आयोजन की तत्काल व्यवस्था कराएं। प्रत्येक ग्राम सभा में नोडल अधिकारी तैनात करें। सभी कनिष्ठ आपूर्ति

अधिकारी भी ग्राम सभाओं मंथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सभी एसडीएम ग्राम सभाओं के आयोजन की मानीटरिंग सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी 31 मई तक न होने पर उन्हें जून माह से खाद्यान्न नहीं मिलेगा। इसके लिए सेल्समैन, समिति प्रबंधक तथा उचित मूल्य दुकान का संचालन करने वालों के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण करके कार्यवाही की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी सभी विकासखण्डों से उचित मूल्य दुकानवार ई केवाईसी अपडेशन की कार्यवाही पूरी कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्रवण एवं दृष्टि बाधित विद्यालय में कक्षा एक में प्रवेश का अवसर

रीवा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शासकीय श्रवण एवं दृष्टि बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा एक में प्रवेश का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में अधीक्षक ने बताया कि श्रवण एवं दृष्टि बाधित बच्चे कक्षा एक में निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश के आवेदन पत्र के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र, युनिक आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, आधार पंजीयन, समग्र आईडी, बैंक खाता संख्या तथा निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

वूमेन फॉर ट्री अभियान के अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं का शैक्षणिक भ्रमण

रीवा। नगर निगम आयुक्त डॉ. सोमध सोवणे के निर्देशानुसार नगर निगम रीवा द्वारा "वूमेन फॉर ट्री" अभियान के अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं को पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने एवं प्रकृति के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से झलबदरी, कुबेर तालाब एवं शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रीवा का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर महिलाओं को जल संरक्षण,



तालाबों के पारिस्थितिक महत्व, तथा पौधारोपण की वैज्ञानिक विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम रीवा के सिटी

मैनेजर श्री अभिमन्यू सिंह, श्री राजेश विश्वकर्मा तथा पीडीएमसी रजिस्टेंट इंजीनियर श्री अर्चित सिंह बघेल, सोशल एक्सपर्ट सुश्री डिल्ल सिंह, फील्ड इंजीनियर सुश्री सोनाली शुक्ला एवं रिफॉर्म एक्सपर्ट श्री ज्योतिरादित्य सिंह मौजूद रहे। इन सभी की उपस्थिति में यह आयोजन प्रेरणादायी एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। महिलाओं ने पूरे उत्साह, समर्पण और लगन के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया।

कमिश्नर ने वनाधिकार की संभागीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

रीवा। वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित रीवा एवं शहडोल जिलों की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ रीवा संभा के कमिश्नर बीएस जामोद ने किया। इस अवसर पर कमिश्नर ने कहा कि जनजातीय परिवार परंपरागत रूप से वनों के संरक्षक रहे हैं। उनकी आजीविका का मुख्य साधन वन रहे हैं। लेकिन जनजातीय परिवारों को आवासीय और खेती की भूमि के पट्टे नहीं मिले हुए थे। वनाधिकार



अधिनियम में हजारों परिवारों को भू अधिकार पत्र देकर उन्हें उस जमीन का मालिक बनाया जिस पर

उनका पीढ़ियों से अधिकार था। वनाधिकार अधिनियम ने जनजातीय परिवारों को वनों की

सुरक्षा करते हुए खेती और अन्य आर्थिक गतिविधियों के अधिकार दिए हैं। इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करके हजारों परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यशाला में मुख्य वन संरक्षक राजेश राय, वन मण्डलाधिकारी, उपायुक्त जनजातीय कार्य श्रीमती उषा अजय सिंह, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला में अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई।

किसानों को कम ब्याज में कृषि ऋण और बीमा सुरक्षा देता है किसान क्रेडिट कार्ड

रीवा। किसानों को फसल की बोनी के समय खाद-बीज, कृषि उपकरण तथा अन्य खेती से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। किसानों के पास अधिक पूंजी न होने के कारण खेती में निवेश करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सबसे कारगर उपाय है। बैंकों के माध्यम से सभी छोटे-बड़े किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं। इसके माध्यम से बैंक किसान को कम अवधि की राशि चार प्रतिशत ब्याज की दर से देती है। किसान फसल आने पर यदि समय पर ऋण राशि चुका देते हैं तो उन्हें अगली फसल के लिए पुनः राशि जारी कर दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड में फसलों

के लिए सरलता से ऋण मिलने के साथ-साथ बीमा सुरक्षा का भी लाभ दिया जाता है। अधिकतम 70 वर्ष तक के किसानों को किसान क्रेडिट कार्डधारी होने पर मृत्यु की दशा में परिजनों को 50 हजार रुपए दिए जाते हैं। दुर्घटना में या अन्य कारण से स्थाई विकलांगता होने पर 25 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि सभी किसान किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के माध्यम से बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जमीन का खसरा आवेदन पत्र के साथ बैंक में प्रस्तुत करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड में किसान का नाम, पता, जमीन की जानकारी तथा अवधि अंकित होती है।

जेल महानिदेशक ने किया केन्द्रीय जेल का निरीक्षण

रीवा। जेल महानिदेशक श्री जीपी सिंह ने केन्द्रीय जेल रीवा का निरीक्षण किया। जेल महानिदेशक ने निरीक्षण के दौरान जेल के विभागीय मद से कराए गए निर्माण कार्यों एवं नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। जेल महानिदेशक ने केन्द्रीय जेल के बंदी वाडों, जेल अस्पताल एवं पाकशाला का भ्रमण किया। महानिदेशक ने बंदियों को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बंदियों की अधिक संख्या के कारण महानिदेशक ने अतिरिक्त बैरक निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रस्तावित निर्माण स्थल का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए।

नलजल योजना की संचालन और संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत उठाएं पंचायतें वाल्व आपरेटरों को समय पर वेतन दें और कार्य कराएं : कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि समूह नलजल योजनाओं का कार्य जिन ग्रामों में पूरा हो गया है वहाँ हर घर में नल का कनेक्शन देकर पानी की प्रतिदिन आपूर्ति कराएं। जिन गांवों में अभी भी कनेक्शन शेष है वहाँ 15 दिवस में सभी घरों में कनेक्शन करा दें। पानी की नियमित आपूर्ति के साथ जल कर की भी वसूली करें। नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतें उठाएं। ग्रामवासियों को

पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की कठिनाई आने पर जल जीवन मिशन की एजेंसी ग्राम पंचायतों को पूरा सहयोग करे। वाल्व आपरेटरों की लापरवाही के कारण गांवों में पानी के वितरण में कठिनाई आ रही है। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उन सभी गांवों में वाल्व आपरेटर की नियुक्ति तत्काल कर दें जहाँ नलजल योजनाएं संचालित हैं। इन्हें ग्राम पंचायतों के माध्यम से नियमित रूप से वेतन का भुगतान करते हुए वाल्व आपरेशन का कार्य कराएं। वाल्व आपरेटर को समय पर वेतन नहीं मिला तो जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को



भी वेतन नहीं मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जलजीवन मिशन द्वारा नल जल योजना की पाइप लाइन की जाँच टैगिंग करके नक्शे उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम पंचायत में कोई भी निर्माण कार्य शुरू होने से पहले उपयंत्री इन नक्शों को अवश्य देखें। जहाँ पाइप लाइन चिन्हित की गई हैं वहाँ निर्माण कार्य न कराएं। निर्माण

कार्यों के कारण जिन स्थानों में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है वहाँ के उपयंत्रियों को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कारण बताओ नोटिस दें। पंचायत के निर्माण कार्य के कारण यदि पेयजल की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होती है तो उसके सुधार का कार्य भी ग्राम पंचायत ही करे। इसके लिए जल कर की राशि और 15वें वित्त की राशि का उपयोग करें। जल जीवन मिशन की निर्माण एजेंसियाँ सुधार कार्य में ग्राम पंचायतों के सहयोग करेंगी। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण की स्वयं निगरानी करें। कलेक्टर ने जिला

पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नलजल योजनाओं के संचालन में लापरवाही बरतने पर नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बाणसागर समूह नलजल योजना तथा टमस समूह नलजल योजना के कार्य में तेजी लाएं। टमस समूह नलजल योजना के निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी रहने पर कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर ने कहा कि टमस समूह नलजल योजना का कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा होना है। इसकी मंथवार प्रगति की कार्ययोजना बनाएं।